3 धामी ने किया बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ

5 पासवान भारतीय राजनीति के एक प्रभावशाली नेता

6 जरूरी है परमाणु जवाबदेही बाधाओं से मुक्ति

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 33 प्रति सोमवार, 22 दिसंबर 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की नई कहानी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में दो वर्षों में परिवर्तनकारी पहलें

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दो वर्षों में "विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़" के संकल्प को साकार करने की दिशा में महिला सशक्तिकरण को विकास की धुरी बनाया है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और निर्णय क्षमता को नीतियों के केंद्र में रखकर राज्य ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की एक नई दिशा तय की है। इन पहलों के चलते छत्तीसगढ़ आज राष्ट्रीय पटल पर महिला विकास के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का स्पष्ट मानना है कि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानित नहीं होंगी, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। उनका कहना है कि बीते दो वर्षों

छत्तीसगढ़ बना आदर्श मॉडल

में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर जो योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं, वे एक समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव हैं। सरकार आगे भी महिलाओं के स्वास्थ्य, आजीविका, सुरक्षा और भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए नीतियां लागू करती रहेगी।

महतारी वंदन योजना से मिली आर्थिक स्वतंत्रता

महिला सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी पहल महतारी वंदन योजना रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को वर्चुअली शुभारंभ की गई। इस योजना के तहत राज्य की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 22 किश्तों में कुल 14,306 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, पोषण, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को सुदृढ़ करना है। (शेष पेज 2 पर)

7 साल में केवल 7 किमी चलेगी मेट्रो

निर्माण की धीमी रफ्तार से खर्च पहुंचा 08 हजार करोड़ के पार, क्या ऐसे होगा विजन 2047 का सपना पूरा?

-विजया पाठक

राजधानीवासी 2019 से मेट्रो का सपना देख रहे हैं। पहली बार जब मेट्रो की आधारशिला रखी गई थी तब लोगों को लगा कि उन्हें भी जल्द अन्य मेट्रो शहरों की तरह मेट्रो की सवारी करने का मौका मिलेगा। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि कछुए की चाल चलने वाला निर्माण कार्य उनके अरमानों पर पानी फेरने वाला है। आज तकरीबन निर्माण कार्य को प्रारंभ हुए 07 साल बीत चुके हैं। इन सात सालों में निर्माण एजेंसी केवल 07 किमी ही चलने लायक ट्रेक बना सकी है। मतलब एक साल में एक किमी। वहीं काम की गति धीमी होने से खर्च भी दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। यहां सवाल उठता है कि इस लेटलतीफी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह ऐसे निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराये? आखिर बढ़े हुए खर्च की भरपायी कौन

करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण कि मेट्रो निर्माण के दौरान भोपाल में जो यातायात अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, उस और ध्यान कौन देगा? सवाल सीधे सरकार से हैं। जिससे लिए सरकार ही जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रोजेक्ट्स की धीमी चाल के साथ ही प्लानिंग और को-ऑर्डिनेशन की कमी की वजह से मेट्रो की लागत 2,500 करोड़ रुपये तक बढ़ चुकी है। यदि प्रोजेक्ट समय से पूरा हो जाता तो मंडीदीप और सीहोर के लिए फंड की कमी नहीं होती। कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया था। भोपाल मेट्रो के 27 किमी के दो कॉरिडोर होंगे और यह काम दो चरण में करने का निर्णय हुआ था। करीब 06 हजार 941 करोड़ की लागत से भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। जो अब निर्माण की धीमी रफ्तार के कारण 08 हजार करोड़ के पार पहुंच गया है। (शेष पेज 2 पर)

किसानों की कर्जमाफी: मध्यप्रदेश में कमलनाथ ने शुरू की थी प्रभावी पहल

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में यदि किसान कल्याण की बात होती है तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम स्वतः ही प्रमुखता से सामने आता है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कमलनाथ ने न केवल नीति निर्धारण के स्तर पर बल्कि धरातल पर भी किसानों के हितों को प्राथमिकता दी बल्कि विशेष रूप से लगभग 18 माह की अपनी सरकार के दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों को जो आर्थिक संबल प्रदान किया, वह आज भी एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त किसान ऋण माफी योजना को लागू किया था। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 51 जिलों के 26 लाख 95 हजार से अधिक किसानों को राहत दी गई। लगभग 11 हजार 646 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि माफ कर किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान की गई। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लाखों परिवारों की चिंता, तनाव और आत्मसम्मान जुड़ा हुआ था। (शेष पेज 2 पर)

26 लाख 95 हजार किसानों के 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक हुए थे माफ

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की नई कहानी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में दो वर्षों में परिवर्तनकारी पहलें

(पेज 1 का शेष)

महिला कल्याण के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की विकास यात्रा में महिलाएं केंद्र बिंदु पर हैं।

संपत्ति में अधिकार और सामाजिक सशक्तिकरण

महिलाओं को आर्थिक ही नहीं, सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर 1 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने का निर्णय उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है और परिवार व समाज में उनकी भूमिका को नई पहचान मिली है। इसी कड़ी में राज्य में 368 महतारी सदनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इन केंद्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण, परामर्श, कौशल विकास और विभिन्न सहायक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक सशक्त मंच तैयार कर रही है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान

स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने मानदेय और प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि समय पर भुगतान सुनिश्चित होने से इन महिलाओं का मनोबल भी बढ़ा है। यह कदम सुशासन और तकनीक के प्रभावी उपयोग का उदाहरण माना जा रहा है।

स्व-सहायता समूहों को नए अवसर

ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए स्व-सहायता समूहों को सशक्त किया गया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ और सूरजपुर जिलों में रेडी-टू-ईट पोषण आहार का कार्य महिला समूहों को सौंपा गया है। इससे महिलाओं को स्थायी रोजगार के साथ आय का सुनिश्चित स्रोत मिला है। इसके अलावा 42,878 महिला स्व-सहायता समूहों को 12,946.65 लाख रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया गया है। इससे महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। दीदी ई-रिक्शा योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना और मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना ने निर्माण श्रमिक परिवारों की महिलाओं और बेटियों के लिए आजीविका के नए रास्ते खोले हैं।

मातृत्व सुरक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

गर्भवती श्रमिक महिलाओं के लिए मिनीमाता महतारी जतन योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरी है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कन्याओं के विवाह में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को और अधिक सशक्त बनाया गया है। अब 50,000 रुपये की सहायता राशि में से 35,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 8,000 कन्याओं के विवाह के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शुचिता योजना के तहत 2,000 स्कूलों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं और 3 लाख से अधिक किशोरियों को स्वच्छता सामग्री वितरित की गई है। हाई स्कूल छात्राओं को साइकिल वितरण के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान कर शिक्षा में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं महिला उद्यमिता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। इन पहलों के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। महिलाएं कृषि, तकनीक और सेवा क्षेत्रों में नए प्रयोग कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने कई अभिनव पहल की हैं।

नवाविहान योजना घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा और मनोसामाजिक सहायता प्रदान कर रही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है, जिसने सखी वन-स्टॉप सेंटर का डिजिटल वर्जन तैयार किया और इसके लिए मानक प्रक्रिया लागू की। 181 महिला हेल्पलाइन और डायल 112 के एकीकृत संचालन से संकट की स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित हो रही है। वहीं सुखद सहारा योजना के तहत 2 लाख 18 हजार से अधिक विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल

नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यूनिटी मॉल महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जशपुर जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित 'जशप्योर' ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयास भी राज्य में महिला उद्यमिता को नई उड़ान दे रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग को वर्ष 2025-26 में 8,245 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला कल्याण और सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण तैयार करना सरकार का संकल्प है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो परिवर्तनकारी कार्य हुए हैं, वे यह सिद्ध करते हैं कि महिलाओं को केंद्र में रखकर किया गया विकास ही सुशासन और प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। छत्तीसगढ़ आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई दिशा, नई उम्मीद और नए परिवर्तन का प्रतीक बनकर देश के सामने एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत कर रहा है।

निर्माण की धीमी रफ्तार से खर्च पहुंचा 08 हजार करोड़ के पार, क्या ऐसे होगा विजन 2047 का सपना पूरा?

(पेज 1 का शेष)

यह भी चिन्तनीय है कि यदि मेट्रो के निर्माण की मौजूदा गति को देखा जाये तो इसे पूर्ण होने में दशकों लगेंगे।

भले ही अब मेट्रो का शुभारंभ हो गया है लेकिन सही मायने में यह सरकार का फेलियर ही है क्योंकि । कई किमी के प्रोजेक्ट में से केवल 07 किमी में मेट्रो चलाकर सरकार जताना चाहती है कि हमने मेट्रो के सपने को साकार कर दिया है। केवल शिलान्यास करने और घोषणा करने से विकास नहीं होता है। इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का भी होना जरूरी है। यहां केवल मेट्रो निर्माण की ही बात नहीं है और भी कई तमाम प्रोजेक्ट हैं जो लेटलतीफी के भेंट चढ़ते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो समय पर पूरा किया गया हो। जिसका सबसे बड़ा खामियाजा इसकी लागत के रूप में सामने आता है।

क्या यही है बीजेपी का विजन 2047?

मोदी सरकार और देश के सभी बीजेपी शासित राज्यों का कहना है कि देश के विकास के लिए विजन 2047 पर काम किया जा रहा है। इसके लिए रोडमेप तैयार किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। यहां विचारणीय है कि क्या ऐसे निर्माण कार्यों की गति से विजन 2047 को हासिल किया जा सकता है। मध्यप्रदेश की मौजूदा मोहन सरकार इसी विजन पर काम करने की बात कह रही है। यदि वाकई में इसी विजन पर सरकार चल रही है तो जमीनी हकीकत से भी दो-चार होना पड़ेगा। केवल बयानबाजी करने से थोड़ी न सफलता हासिल होती है। विधानसभा चुनाव 2023 के ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल में मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर क्रेडिट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवराज ने मेट्रो का क्रेडिट लेते हुए कहा था कि हमने गड्ढों वाला मध्य प्रदेश को मेट्रो वाला बनाया है। हालांकि बाद में शिवराज के इस बयान पर काफी विवाद हुआ और कांग्रेस नेताओं ने इसे कमलनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए उसे कांग्रेस और प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताई थी।

आखिर भाजपा सरकार ने क्यों लेट किया प्रोजेक्ट?

सवाल यह है कि जिस प्रदेश को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सितंबर 2019 में ही भोपाल के लिए भोज मेट्रो और इंदौर के लिए इंदौर मेट्रो का तोहफा दिया था और दिसंबर 2022 में भोपाल में मेट्रो ट्रेन और अगस्त 2023 में इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलनी थी, वह समय पर क्यों नहीं चल सकी। आज जब भोपाल और इंदौर की जनता को मेट्रो ट्रेन का सफर करना था तब उन्हें सिर्फ ट्रायल रन का तमाशा क्यों दिखाया जा रहा है?

किसानों की कर्जमाफीः मध्यप्रदेश में कमलनाथ ने शुरू की थी प्रभावी पहल

(पेज 1 का शेष)

कर्ज माफी से किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिली और उन्हें दोबारा सम्मानपूर्वक खेती करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से यदि कमलनाथ अपना कार्यकाल पूरा करते तो प्रदेश के किसानों का समस्त प्रकार का शासकीय कर्ज माफ कर देते।

मध्यप्रदेश का किसान लंबे समय से साहूकारों और व्यापारियों के कर्ज के जाल में फंसा हुआ था। फसल की अनिश्चितता, मौसम की मार, उचित मूल्य न मिलना और बढ़ती लागत ने किसान को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया था। ऐसे कठिन समय में कमलनाथ ने किसानों की इस पीड़ा को समझा और सत्ता संभालते ही इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद कमलनाथ ने सबसे पहले जिस फाइल पर हस्ताक्षर किए, वह थी किसानों की ऋण माफी से संबंधित फाइल थी। जैसा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। यह कदम न केवल एक प्रशासनिक निर्णय था, बल्कि यह उनके किसान-केन्द्रित दृष्टिकोण और संवेदनशील नेतृत्व का प्रतीक भी था। यह कमलनाथ ही थे जिन्होंने सबसे पहले कृषि प्रधान प्रदेश में किसानों के हित में इतना बड़ा फैसला लिया था। इस कर्जमाफी से लाखों किसानों को राहत मिली और जो किसान डिफाल्टर थे उनकी आगे की राह आसान हुई। प्रदेश के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित है।

किसानों की आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम

कमलनाथ का मानना था कि किसान को केवल सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। ऋणमाफी के माध्यम से उन्होंने किसानों को नई शुरुआत का अवसर दिया। इससे किसान बीज, खाद और आधुनिक तकनीकों में निवेश कर सका और उसकी उत्पादकता में सुधार हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में इस योजना की अहम भूमिका रही। जब किसानों के हाथ में पैसा आया, तो बाजारों में क्रय शक्ति बढ़ी और इससे गांवों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई।

विपक्ष का दुष्प्रचार और सच्चाई

कमलनाथ की इस ऐतिहासिक पहल से झल्लाकर बीजेपी के कई नेताओं ने कर्जमाफी को लेकर दुष्प्रचार किया। यह कहा गया कि कर्ज माफी पूरी तरह लागू नहीं हुई या यह केवल दिखावा थी। जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश में सबसे अधिक किसानों को एक साथ कर्ज माफी देने का रिकॉर्ड कमलनाथ सरकार ने ही कायम किया। दुष्प्रचार के बावजूद तथ्य यह रहे कि लाखों किसानों को वास्तविक लाभ मिला और उनके बैंक खातों से कर्ज की राशि समाप्त हुई। स्वयं किसान समुदाय ने अनेक मंचों पर इस योजना की सराहना की।

केन्द्रीय मंत्री रहते हुए भी किसानों के लिए योगदान

कमलनाथ का किसान हितैषी दृष्टिकोण केवल मुख्यमंत्री पद तक सीमित नहीं रहा। इससे पहले जब वे केन्द्र सरकार में मंत्री थे, तब भी उन्होंने मध्यप्रदेश के ग्रामीण और किसान हितों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन में कमलनाथ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस योजना के माध्यम से गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, जिससे किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा हुई। बेहतर सड़क संपर्क से परिवहन लागत घटी और किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलने लगा। ग्रामीण सड़कों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को भी गांवों तक पहुंचाया, जिससे समग्र ग्रामीण विकास को गति मिली।

संवेदनशील राजनीति का उदाहरण

कमलनाथ की राजनीति का मूल आधार संवेदनशीलता और समावेशिता रहा है। वे किसानों को केवल वोट बैंक के रूप में नहीं, बल्कि प्रदेश की रीढ़ मानते हैं। उनकी नीतियों में किसान, मजदूर और ग्रामीण समाज की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता में रहा। कर्ज माफी, फसल बीमा, उचित समर्थन मूल्य और ग्रामीण अधोसंरचना ये सभी उनके किसान-केन्द्रित दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे।

भविष्य के लिए प्रेरणा

कमलनाथ द्वारा किए गए कार्य आज भी यह प्रेरणा देते हैं कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो किसानों की स्थिति में वास्तविक सुधार किया जा सकता है। उनकी सरकार ने यह साबित किया कि सीमित समय में भी बड़े और प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं। मध्यप्रदेश के किसान आज भी उस दौर को याद करते हैं, जब सरकार ने उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें आर्थिक संबल दिया। यह केवल एक सरकार की उपलब्धि नहीं, बल्कि किसान और सरकार के बीच विश्वास का उदाहरण था।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 18 माह के कार्यकाल में किसानों के हित में जो कदम उठाए, वे मध्यप्रदेश की राजनीति में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। कर्ज माफी से लेकर ग्रामीण सड़कों तक, उन्होंने हर स्तर पर किसान कल्याण को प्राथमिकता दी। आज जब किसान संकट की चर्चा होती है तो कमलनाथ का नाम एक ऐसे नेता के रूप में सामने आता है, जिसने नीतियों को जमीन पर उतारकर दिखाया। उनका योगदान न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मानक और प्रेरणा बना रहेगा।

एफ़आईआर दर्ज करने के बावजूद भी डॉ. पंकज वत्स और उनके पिता राम रत्न शर्मा द्वारा पीड़ित युवती को धमकी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. नई दिल्ली। पीड़ित युवती, जो एमएनसी में कार्यरत है, ने डॉ. पंकज वत्स एंव उनके पिता राम रत्न शर्मा पर एफआईआर दिल्ली पुलिस स्टेशन में करवाई है। शादी का झांसा देकर डॉ. वत्स ने पीड़ित युवती से संबंध बनाए। डॉ. पंकज वत्स पीड़ित युवती को हमेशा यह समझाने में कामयाब रहा कि मेरी पत्नी दीप्ति वत्स से कोई पति-पत्नी का संबंध नहीं है। मेरी पत्नी मुझे अनादर करती रहती है। इसलिए मैं उसको तलाक देकर तुम्हें पत्नी बनाऊँगा और तुम हमारे परिवार के साथ सदा जिंदगी व्यतित करोगी। डॉ. पंकज वत्स के पिता (राम रत्न) इस मामले में अपने बेटे का पक्ष रखकर हमेशा उसे सपोर्ट करता रहा है, साथ-साथ डॉ. पंकज की पत्नी दीप्ति वत्स तथा उसकी बहन भी इस मामले में शामिल है। पीड़िता ने बताया डॉ. वत्स व राम रत्न शर्मा ने मुझे और मेरे परिवार को काफी धमका रहा है। बाद में काफी विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने मुझे रेस्टोरेन्ट में मिलने को कहा और डॉ. पंकज वत्स व उनके पिता राम रत्न ने आश्वासन दिया की पुरानी बातें भूलकर तुम दोनों मिलके एक नई खुशहाली जिंदगी जियो और मेरी शुभकामनाए तुम लोगों के साथ सदा बनी रहेगी। लेकिन कुछ मिंटो के बाद दोनों बाप-बेटा का मिजाज बदल गया और कहा कि तुम एक एग्रीमेंट हम लोगों के साथ कर लो और मेरा बेटा डॉ. पंकज वत्स से कोई संबंध रहा ही नहीं है। लेकिन इस तरह के एग्रीमेंट नहीं मानने के बाद वो दोनों पुत्र व पिता पीड़ित युवती को गालियां देकर निकाल गए।

मुख्यमंत्री धामी द्वारा बैंडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय बैंडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब हमारी देवभूमि खेलभूमि के तौर पर आगे बढ़ रही है। हम आने वाले समय में खेलों में अच्छा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शासकीय कार्यों की व्यस्तता के बीच कार्मिकों द्वारा खेल गतिविधियों को अपनाना बेहद जरूरी है। क्योंकि खेल जीवन में अनुशासन लाने के साथ-साथ तनाव को दूर करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। उन्होंने कहा कि निरोगी रहना मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और खेल इस दिशा में सबसे प्रभावी माध्यम है। बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, परेड ग्राउंड, देहरादून में उत्तराखण्ड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित 10वीं अन्तर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता–2025 का सीएम धामी ने शुभारम्भ किया। साथ ही उन्होंने यहां बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन भी खेला। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अन्तर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता भविष्य में भी अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी और कर्मचारियों-अधिकारियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी।

युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिले अवसर

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। प्रतियोगिता में राज्य के 42 विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश के सामने एक उदाहरण बनकर उभर रहा है। राज्य परिवर्तन की ओर अग्रसर है और नवाचारों, ऐतिहासिक निर्णयों तथा जनहितकारी नीतियों के माध्यम से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया गया, जिससे राज्य में खेल अवसंरचना और सुविधाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में खेलों को प्रोत्साहित कर राज्य को 'खेल भूमि' के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सके।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पारदर्शी धान खरीदी से किसानों को मिल रहा आर्थिक संबल

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों का जीवंत प्रमाण जीपीएम जिले के उपार्जन केंद्र गौरेला में दिखाई दे रहा है, जहां समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू और पारदर्शी ढंग से चल रही है। ग्राम नेवसा मदरवानी के किसान जगन्नाथ यादव ने इस व्यवस्था की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व में लागू की गई यह पारदर्शी नीति न केवल किसानों को उनकी मेहनत का सही फल दे रही है, बल्कि उन्हें वास्तविक खुशहाली की राह पर ले जा रही है। किसान जगन्नाथ यादव ने विस्तार से बताया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो रही है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बड़ा माध्यम बन गई है।

प्रति एकड़ औसतन 21 क्विंटल धान उत्पादन से किसानों को पर्याप्त आय सुनिश्चित हो रही है। इस वर्ष उन्होंने अपनी 4 एकड़ 46 डिसमिल भूमि में धान की खेती की और प्रथम टोकन के तहत 50 क्विंटल धान उपार्जन केंद्र गौरेला लेकर आए हैं। यादव ने कहा कि ''टोकन तुहर हाथ'' ऐप की बदौलत घर बैठे टोकन प्राप्त हो जाने से उन्हे बहुत सहुलियत हो रही है, जिससे उपार्जन केंद्रों के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे समय, श्रम और ईंधन की बचत हो रही है। पूरी खरीदी प्रक्रिया अत्यंत सहज और त्रुटिरहित है। न तो कोई गड़बड़ी, न देरी और न ही तनाव का नामोनिशान। त्वरित भुगतान और पूर्ण पारदर्शिता ने किसानों का सरकार पर विश्वास और दृढ़ कर दिया है। जगन्नाथ यादव सहित क्षेत्र के अन्य किसान इस व्यवस्था से उत्साहित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल किसान कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है, जो न केवल धान खरीदी को पारदर्शी बना रही है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित कर रही है। जिले के अन्य उपार्जन केंद्रों पर भी यही उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां हजारों किसान लाभ उठा रहे हैं।

23-25 दिसम्बर तक राज्य युवा महोत्सव, 3100 युवा करेंगे भागीदारी

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। न्यायधानी बिलासपुर में आगामी 23 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक आयोजित राज्य युवा महोत्सव-2025 में 3100 युवा भागीदारी करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिला स्तरीय युवा उत्सव के विजेता प्रतिभागी 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। राज्य युवा महोत्सव के विजेता प्रतिभागी अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। 23 दिसम्बर को महोत्सव के उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में होने वाले प्रथम खेलो इण्डिया ट्रायबल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी भी होगी। तीन दिवसीय इस आयोजन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक एवं मंचीय कार्यक्रम भी होंगे। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में राज्य युवा महोत्सव के दौरान होने वाले प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने अपने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया।

छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने, उनकी प्रतिभा

को निखारने तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करने राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2026 के तारतम्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में युवा महोत्सव का जिला स्तरीय आयोजन 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक किया गया था। जिला स्तर पर 14 विभिन्न विधाओं के विजेता प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में हिस्सेदारी करेंगे। राज्य युवा महोत्सव में 14 विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें 8 दलीय विधाएं और 6 एकल विधाएं शामिल हैं। दलीय विधाओं में लोकनृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुआ नृत्य, करमा नृत्य, लोकगीत, रॉक बैंड और एकांकी की प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं एकल विधाओं में वाद-विवाद, कहानी लेखन, चित्रकला, कविता लेखन, नवाचार (साइंस मेला) और पारंपरिक वेशभूषा शामिल हैं। राज्य युवा महोत्सव में दलीय विधाओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को 20 हजार रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 15 हजार रुपए एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 10 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। एकल विधाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 5 हजार रुपए, 3 हजार रुपए एवं 2 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। महोत्सव में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को एक-एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य युवा महोत्सव में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की 5 विधाओं लोकनृत्य, लोकगीत, वाद-विवाद, चित्रकला और कविता लेखन के विजेता प्रतिभागी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव-2026 में भागीदारी करेंगे। राज्य युवा महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध कलाकारों के गायन, बैण्ड परफॉर्मेंस, कवि सम्मेलन जैसे विविध आयोजन भी होंगे। 23 दिसम्बर को उद्घाटन समारोह के दिन राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक आरूग बैण्ड (श्री अनुज शर्मा) की प्रस्तुति तथा नारायणपुर के प्रसिद्ध मल्लखंब का प्रदर्शन किया जाएगा। 23 दिसम्बर को ही बिलासपुर पुलिस ग्राउण्ड में रात साढ़े 8 बजे से कवि सम्मेलन होगा, जिसमें प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास एवं अन्य कवि कविता पाठ करेंगे।

सम्पादकीय

डॉ. मोहन यादव के दो वर्षः सेवा, सुशासन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल

मध्यप्रदेश की राजनीति में डॉ. मोहन यादव का मुख्यमंत्री के रूप में उदय एक ऐसे समय में हुआ, जब राज्य को स्थिर प्रशासन, स्पष्ट नेतृत्व और विकास की नई दृष्टि की आवश्यकता थी। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद बीते दो वर्षों में डॉ. मोहन यादव ने स्वयं को एक कर्मठ, वैचारिक रूप से स्पष्ट और जनसंवेदनशील नेता के रूप में स्थापित किया है। उनका कार्यकाल "सेवा, सुशासन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद" के त्रिसूत्र पर केंद्रित दिखाई देता है। डॉ. मोहन यादव की सबसे बड़ी विशेषता उनका प्रशासनिक अनुशासन और निर्णय क्षमता रही है। उन्होंने सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार का केंद्र बिंदु जनता होगी, न कि सत्ता का प्रदर्शन। अफसरशाही में जवाबदेही तय करना, समयबद्ध निर्णय और योजनाओं की नियमित समीक्षा उनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा बनी। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया। संगठित अपराध, माफिया गतिविधियों और अवैध उत्खनन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई। इससे आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा और प्रशासन की साख मजबूत हुई। सुशासन का यह मॉडल "डर से नहीं, विश्वास से शासन" की अवधारणा को आगे बढ़ाता है। डॉ. मोहन यादव का कार्यकाल सेवा-प्रधान दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। सरकार की योजनाओं का फोकस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर रहा। महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और किसान हित सरकार की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहे। लाड़ली बहना योजना को और अधिक प्रभावी बनाते हुए सरकार ने महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को सामाजिक सम्मान से जोड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का व्यापक असर देखने को मिला, जिससे महिलाओं की घरेलू और सामाजिक भूमिका में सकारात्मक परिवर्तन आया। किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं, फसल बीमा और समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए गए। सरकार ने यह संदेश दिया कि किसान केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देकर ग्रामीण आय बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं शिक्षाविद् पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसका प्रभाव उनकी शिक्षा नीतियों में स्पष्ट दिखता है। नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने, उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार को प्रोत्साहन देने तथा युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों से जोड़ने की पहल हुई, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और समयबद्ध आयोजन ने सरकार की नीयत को भी स्पष्ट किया। डॉ. मोहन यादव का कार्यकाल मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सशक्त करने के लिए भी याद किया जाएगा। उज्जैन, जो स्वयं मुख्यमंत्री की कर्मभूमि रही है, उसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में राष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास तेज हुए। महाकाल लोक के विस्तार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिली।

सियासी गहमागहमी

शिवराज सिंह चौहान की बढ़ती सुरक्षा व्यवस्था ने चौंकाया

शिवराज की बढ़ती सुरक्षा ने राजनीति के गलियारों में वही असर डाला, जो अचानक सायरन बजने से आम आदमी के दिल पर पड़ता है। भोपाल से दिल्ली तक कानाफूसी शुरू हो गई- "कुछ तो बड़ा होने वाला है!" सुरक्षा बढ़ी तो स्वाभाविक है, कल्पनाएँ भी बढ़ीं। नेताओं, कार्यकर्ताओं और विश्लेषकों ने बिना देर किए निष्कर्ष निकाल लिया कि अब तो शिवराज सिंह चौहान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने ही वाले हैं। किसी ने कहा, "इतनी सुरक्षा तो दिल्ली बुलावे से पहले ही मिलती है।" किसी ने जोड़ा, "भाई, ये तो साफ संकेत है।" कार्यकर्ताओं ने मिठाइयों के डिब्बों की मानसिक बुकिंग तक कर ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे जाने लगे- "अध्यक्ष शिवराज" सुनने में कितना अच्छा लगता है! कुछ उत्साही समर्थकों ने तो यह भी तय कर लिया कि अब मध्यप्रदेश की राजनीति इतिहास बन चुकी है। लेकिन राजनीति में सुरक्षा बढ़ना हमेशा पद बढ़ने का संकेत नहीं होता। कई बार यह सिर्फ सुरक्षा बढ़ना ही होता है- ना कम, ना ज्यादा।

अन्नदाता को प्राथमिकता देने वाली थी कमलनाथ की सरकार

कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही किसानों को आर्थिक राहत देकर यह संदेश दिया था कि उनकी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश का अन्नदाता होगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कर्जमाफी की घोषणा कर उन्होंने चुनावी वादे को नीतिगत निर्णय में बदलने का प्रयास किया। यह कदम केवल प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि किसानों के प्रति राजनीतिक संवेदनशीलता और भरोसे का प्रतीक भी माना गया। मध्यप्रदेश लंबे समय से कृषि संकट, कर्ज के बोझ और लागत बनाम उत्पादन मूल्य की समस्या से जूझ रहा था। ऐसे में कमलनाथ का पहला निर्णय किसानों को राहत देने से जुड़ा होना स्वाभाविक भी था और प्रतीकात्मक भी। इससे ग्रामीण अंचलों में यह उम्मीद जगी कि सरकार किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुनेगी और समाधान निकालेगी। हालांकि यह राहत योजना पूरी तरह लागू हो पाती, उससे पहले ही सरकार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गई। इसके बावजूद यह तथ्य नकारा नहीं जा सकता कि सत्ता संभालते ही किसानों के पक्ष में लिया गया निर्णय कमलनाथ सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है। आलोचकों ने योजना के क्रियान्वयन और सीमाओं पर सवाल उठाए, लेकिन समर्थकों के लिए यह निर्णय किसान हितैषी सोच का प्रमाण था।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है - महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से।

मनरेगा, महात्मा गांधी के ग्राम-स्वराज के सपने का जीवंत रूप है - करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

समस्त भोपालवासियों को मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं।

मुझे खुशी है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में मैंने जो पहल की थी और मुख्यमंत्री के रूप में जिस परियोजना का शिलान्यास किया था, आज वह परियोजना मूर्त रूप ले रही है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता रहे हैं

समता पाठक/जगत प्रवाह

रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता थे। उनका जीवन न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों के लिए किए गए उनके संघर्ष के लिए भी जाना जाता है। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जीवन को समाज के निचले वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका जन्म बिहार राज्य के एक छोटे से गाँव में हुआ था और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर राजनीति में उच्च स्थान प्राप्त किया। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार राज्य के खगड़िया जिले के शहबाजपुर गाँव में हुआ था। उनका परिवार एक पिछड़ी जाति से था, और उन्होंने गरीब और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से आने के बावजूद शिक्षा में रुचि दिखाई। उनके पिता का नाम महेन्द्र पासवान था और वे एक किसान थे। बचपन से ही पासवान ने अपनी कड़ी मेहनत और शिक्षा की ओर लगन को देखा और आगे चलकर राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई।

रामविलास पासवान की प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा में रुचि और समाज में सुधार की भावना के कारण उन्होंने राजनीति को अपना माध्यम बनाया। रामविलास पासवान का राजनीति में कदम रखना 1960 के दशक के अंत में हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के युवा संगठन से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। हालांकि, 1970 के दशक में इमरजेंसी (1975-77) के दौरान पासवान ने यह महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी में जातिवाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी।

1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ, तब रामविलास पासवान ने इसके साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक यात्रा को एक नई दिशा दी। उन्होंने जनता पार्टी के तहत बिहार के एक प्रभावी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके सामाजिक न्याय के प्रति संघर्ष ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बना दिया, खासकर दलित समुदाय के बीच। रामविलास पासवान का वास्तविक राजनीतिक प्रभाव 1990 के दशक में दिखना शुरू हुआ, जब वह केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए। 1996 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) की स्थापना की। उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों की रक्षा करना था। पासवान ने भारतीय राजनीति में अनेक बार महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय पदों पर कार्य किया। 1996 में, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2000 में, उन्होंने शरद यादव के साथ मिलकर एक नई राजनीतिक दिशा की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने 2004 और 2009 में भी केंद्र सरकार में मंत्री पद संभाले।

केंद्र सरकार में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका प्रमुख उद्देश्य गरीबों और विशेष रूप से दलितों को सशक्त बनाना था। रामविलास पासवान का जीवन सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण का उदाहरण था। वे हमेशा दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने संविधान में दिए गए दलितों के अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया। पासवान ने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दलितों को समाज में समान दर्जा मिले और उनके साथ भेदभाव न हो। उनका यह मानना था कि भारतीय समाज में जातिवाद का विरोध किया जाना चाहिए और इसे समाप्त करने के लिए शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुधार आवश्यक है।

रामविलास पासवान का व्यक्तिगत जीवन भी अत्यधिक साधारण था। वह एक कट्टर समाजवादी नेता थे और उनका जीवन उनके कार्यों और आदर्शों से प्रेरित था। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी रीता पासवान और उनके दो बेटे चिराग पासवान और आशा पासवान हैं। चिराग पासवान, जो कि एक अभिनेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के अध्यक्ष भी हैं। रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को हुआ। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति थी। उनके जाने के बाद उनकी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, को उनके बेटे चिराग पासवान ने नेतृत्व किया। रामविलास पासवान का योगदान भारतीय राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा, खासकर उनकी भूमिका दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा में।

ऊर्जा संरक्षण:

आज का अनुशासन, कल की राष्ट्रीय सुरक्षा

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

ऊर्जा संरक्षण आज केवल पर्यावरण या घरेलू बिजली बिल का विषय नहीं रह गया है। यह अब राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता, रणनीतिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ प्रश्न बन चुका है। 14 दिसंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हमें यह समझने का अवसर देता है कि ऊर्जा की बचत भी ऊर्जा उत्पादन का ही एक प्रभावी और जिम्मेदार स्वरूप है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ऊर्जा संरक्षण भारत के लिए एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य राष्ट्रीय नीति बन चुका है। ऊर्जा संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी है याद रखिये- एक यूनिट बिजली बचाना, सवा यूनिट उत्पादन के बराबर है।

ऊर्जा संरक्षण का मूल मंत्र

सरल शब्दों में कहा जाए तो "कम संसाधनों में अधिक उत्पादन और कम प्रदूषण में अधिक विकास" यही ऊर्जा संरक्षण का मूल दर्शन है। यह दर्शन हमें बताता है कि विकास और पर्यावरण परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि संतुलन के साथ आगे बढ़ने पर एक-दूसरे को सशक्त करते हैं।

एक दूरदर्शी शुरुआत

भारत में ऊर्जा संरक्षण की संगठित शुरुआत वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के लागू होने के साथ हुई। इसी अधिनियम के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency – BEE) का गठन किया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में चिह्नित करने का उद्देश्य स्पष्ट था, सीमित ऊर्जा संसाधनों और निरंतर बढ़ती मांग के बीच संतुलन स्थापित करना। यह पहल उस दूरदर्शी सोच को दर्शाती है, जिसमें दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता दी गई।

उद्देश्य: बचत से समृद्धि की ओर

ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इसके प्रमुख लक्ष्यों में उद्योगों, संस्थानों और आम नागरिकों में ऊर्जा साक्षरता बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित कर पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना तथा आयातित ईंधन (Imported Fuel) पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना शामिल है। ऊर्जा की प्रत्येक बचाई गई इकाई आर्थिक संसाधनों की बचत के साथ-साथ पर्यावरणीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

वर्तमान उपलब्धियाँ: बदलाव की ठोस तस्वीर

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उजाला योजना के अंतर्गत करोड़ों LED बल्बों के वितरण से बिजली की खपत में भारी कमी आई है, जिससे आम उपभोक्ता का बिजली बिल भी घटा है। वहीं, उद्योगों के लिए लागू की गई PAT योजना (Perform, Achieve, Trade) ने ऊर्जा दक्षता को प्रतिस्पर्धी और मापनीय बनाया है। इन प्रयासों ने यह सिद्ध किया है कि सही नीति और तकनीक मिलकर बड़े स्तर पर परिवर्तन ला सकती है।

शासकीय प्रयास: नीति से क्रियान्वयन तक

भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को केवल कागजी नीति तक सीमित नहीं रखा है। स्टार-रेटिंग प्रणाली, ऊर्जा दक्ष भवन संहिता (ECBC), राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा बचत को संस्थागत रूप दिया गया है। ये सभी प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि ऊर्जा दक्षता विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बने।

योजनाएँ: भविष्य की तैयारी

सरकारी योजनाएँ केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं हैं, बल्कि भविष्य की ठोस तैयारी भी हैं। सौर रूफटॉप योजना के माध्यम से अब आम नागरिक न केवल ऊर्जा उपभोक्ता, बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी बन रहा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध वितरण को संभव बना रहा है। वहीं, FAME योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम की जा रही है।

जनभागीदारी: परिवर्तन की वास्तविक शक्ति

ऊर्जा संरक्षण की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार जनभागीदारी है। सरकार नीतियाँ बना सकती है और संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन नागरिकों की दैनिक आदतों से आता है। पाँच-स्टार रेटिंग वाले उपकरणों का उपयोग, प्राकृतिक रोशनी को प्राथमिकता देना, निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन या कार-पूलिंग को अपनाना- ये छोटे कदम मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा-संस्कृति का निर्माण करते हैं।

भविष्य का परिदृश्य: ऊर्जा-सुरक्षित भारत

आने वाला समय ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से निर्णायक होगा। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के बीच ऊर्जा संरक्षण ही स्थायी समाधान है। तकनीकी रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि एक यूनिट बिजली की बचत, ट्रांसमिशन और वितरण हानियों को घटाकर लगभग 1.3 यूनिट बिजली उत्पादन के बराबर योगदान देती है। यही कारण है कि ऊर्जा संरक्षण को आज महत्व दिया जा रहा है।

राष्ट्र धर्म के रूप में ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण किसी मजबूरी का परिणाम नहीं, बल्कि एक अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक होने का प्रतीक है। जिस राष्ट्र के नागरिक ऊर्जा के प्रति सजग होते हैं, वही राष्ट्र दीर्घकाल में सशक्त और आत्मनिर्भर बनता है। याद रखना आवश्यक है- ऊर्जा संरक्षण आज का अनुशासन है और कल की समृद्धि।

परमाणु ऊर्जा शांति विधेयक- 2025

जरूरी है परमाणु जवाबदेही बाधाओं से मुक्ति

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष के तमाम विरोध और हंगामे के बावजूद 'शांति विधेयक- 2025' अर्थात 'भारत परिवर्तन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन तथा उन्नयन विधेयक- 2025' लोकसभा से पारित करा लिया। इस विधेयक का उद्देष्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त करना है। दरअसल भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने की दृष्टि से ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े लक्ष्य को प्राप्ती के लिए निजी कंपनियों का सहयोग जरूरी है। अकेली सरकारी संस्थाओं के बूते इस मकसद को पूरा करना मुमकिन नहीं है। अतएव इस नए विधेयक के आने से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद की जा रही है। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित कानूनी ढांचा तैयार करेगा। फलस्वरूप निजी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर सकेंगी। इस क्षेत्र में अभी तक परमाणु ऊर्जा विभाग का ही कब्जा है। इस विधेयक के बाद अतिरिक्त बिजली उत्पादन, ग्रिड एकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा।

नागरिक दायित्व अधिनियम (सीएलएनडीए) 2010 में दो महत्वपूर्ण संषोधन सरकार कर सकती है। इन दो संषोधनों को बड़े सुधारों के रूप में देखा जा रहा है। इस संशोधन के तहत परमाणु संयंत्रों को उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी सीमित की जा सकती है। मसलन यदि कोई दुर्घटना होती है तो उनकी जिम्मेदारी अनुबंध की मूल राशि और एक निर्धारित समय तक ही सीमित रहेगी। इस परिप्रेक्ष्य में बतौर उदाहरण विदेशी कंपनी जैसे जीई-हिताची वेस्टिंग हाउस को इस कानून के कारण निवेश में हिचक होती रही है। दूसरा संशोधन परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में प्रस्तावित है। यह कानून फिलहाल केवल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को ही परमाणु संयंत्र चलाने की अनुमति देता है। इसे संशोधित किया जाता है तो निजी कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन की अनुमति मिल जाएगी। इस परिवर्तन से विदेशी कंपनियों के लिए भविष्य के परमाणु प्रोजेक्ट में अंषिक हिस्सेदारी का द्वार खुल जाएगा। साफ है, ये उपाय हो जाते हैं तो परमाणु उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं तो बढ़ जाएंगी, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु दुर्घटना होने पर कंपनियों को नागरिक जवाबदेही से मुक्ति मिल जाएगी। याद रहे मनमोहन सिंह सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत-अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते के बाद जो राजनीतिक तूफान उठा था, उसके चलते संयुक्त प्रगतिषील गठबंधन-1 सरकार गिरते-गिरते बची थी।

दरअसल सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बाधा मुक्त इसलिए करना चाहती है जिससे 2047 तक सौ गीगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। इसी लक्ष्य पूर्ति के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाना चाहती है। इसीलिए 2024-25 के आम बजट में लघु परमाणु संयंत्रों के लिए सरकार ने बड़े बजट का प्रावधान किया था। इस क्षेत्र में नया प्रयोग करते हुए पहली बार निजी कंपनियों को लघु परमाणु संयंत्र समूचे देष में स्थापित करने का अवसर दिया जाएगा। कालांतर में विदेशी कंपनियों को भी परमाणु संयंत्र लगाने की अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही मॉड्यूलर (प्रतिरूपक) रिएक्टर के आधुनिकीकरण के लिए शोध और विकास पर भी धनराशि खर्च की जाएगी। जिससे परमाणु ऊर्जा में नई प्रौद्योगिकी का विकास हो, इसे पीपीपी मॉडल पर क्रियांवित किया जाएगा। इसका उद्देष्य देष में स्वच्छ एवं वैकल्पिक बिजली को बढ़ावा देना है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर गए थे, तब भारत में छोटे परमाणु संयंत्र लगाने और भारत में ही उत्पादन करने का समझौता हुआ था। एआई के दौर में ऊर्जा की खपत असाधारण रूप से बढ़ने की उम्मीद है। यह एक कंप्यूटर की भाशा का कृत्रिम बुद्धि से जुड़ा मॉडल है। भाशा मॉडल ऐसे मषीन लर्निंग मॉडल हैं, जो मानव भाशा के पाठ को समझ सकते है और सुजित भी कर सकते हैं। ये मॉडल भाशा के बड़े डेटा भंडार का विष्लेशण करने पर भी सक्षम होते हैं। सुपर और क्वांटम कंप्यूटर में इसी एआई की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए परमाणु ऊर्जा की जरूरत लघु परमाणु संयंत्रों से ही संभव हैं। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में इसे क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है।

विकसित भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक बड़ी जरूरत है। इसलिए सरकार सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। ऑप्रिशन सिंदूर के बाद जिस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी और गैर-सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया था, उन आयुधों के निर्माण और संचालन के लिए भी परमाणु ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में सौर और पवन ऊर्जा पर सरकार पहले ही काफी कुछ कर चुकी है। अतएव अब फोकस परमाणु ऊर्जा पर केंद्रित है। क्योंकि इसमें संभावनाएं अधिक हैं। आम बजट पेष करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा सुरक्षा को सरकार की नौ प्राथमिकताओं में गिनाया था। ऊर्जा बदलाव के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की बात भी कही गई है। इससे यह तय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे-धीरे अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का महत्व बढ़ रहा है। यह दस्तावेज ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान खोजेगा। अतएव इसी परिप्रेक्ष्य में निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसी धातुओं के उत्पादों के आयात पर शुल्क घटाया है। इन उत्पादों का प्रयोग परमाणु और सौर ऊर्जा के साथ दूसरे ऊर्जा उत्सर्जन उपायों में भी होता है। आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करने में आसानी होगी। यही नहीं परमाणु ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा और अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली 25 धातुओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यानी छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के रास्ते साफ किए जा रहे हैं।

भारत में एक ओर अर्से से अटकी परमाणु बिजली परियोजनाओं में विद्युत का उत्पादन शुरू हो रहा है, वहीं निजी निवेश से परमाणु ऊर्जा बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत जिले के तापी काकरापार में 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने 700-700 मेगावाट बिजली उत्पादन के दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र 22 फरवरी 2024 को राष्ट्र को समर्पित कर दिए हैं। ये देश के पहले स्वदेषी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ये संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 10.4 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे। जो गुजरात में बिजली की आपूर्ति के साथ अन्य प्रांतों को भी बिजली देंगे। ये संयंत्र शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। भारत सरकार के उपक्रम परमाणु ऊर्जा निगम ने मध्यप्रदेश में चार नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। जल्दी ही ये संयंत्र नीमच, देवास, सिवनी और शिवपुरी में लगेंगे। सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। इन संयंत्रों के शुरू हो जाने पर 1200 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली पैदा होगी। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता पिछले 10 साल में करीब दोगुनी हो चुकी है। 2031 तक इसके तीन गुना होने की उम्मीद है।

हालांकि परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न खतरों की आशंकाएं भी एकदम बेबुनियाद नहीं हैं। इसलिए परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। रूस के चेर्नोबिल और जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में हादसे के बाद इस तरह की चिंताएं जरूरी हैं। क्योंकि वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद प्राकृतिक आपदाओं के सामने हम बौने हैं। जापान में महज दस सेकेंड के लिए आई सुनामी नामक विराट आपदा ने फुकुशिमा की वैज्ञानिक उपलब्धियों को चकनाचूर कर दिया था। सृष्टि को संजीवनी देने वाले तत्व हवा, पानी और अग्नि जब न्यूनतम मर्यादाओं की सीमा लांघकर भीषण विराटता रचते हैं तो दसों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ विनाशलीला का मंजर दिखाई देता है। इसलिए जरुरी है कि परमाणु रिएक्टर प्रदायक कंपनियों को कड़ी षर्तों के तहत मुआवजे के प्रावधान निर्धारित हों या फिर बीमा कंपनियों को दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति से जोड़ा जाए। परमाणु बिजली संयंत्रों में ग्रेफाइट मॉडरेट के रुप में प्रयोग होता है। जिसमें पानी की बहुत थोड़ी मात्रा विलय करने से हाइडोजन और ऑक्सीजन के विखण्डन के समय बहुत अधिक तापमान के साथ उर्जा निकलती है। इस उर्जा का दबाव टर्बाइन को तीव्रतम गति से घुमाने का काम करता है। नतीजतन बिजली उत्पन्न होती है। रिएक्टरों के इस उच्चतम तापमान को एक सेंटीग्रेट तक काबू में रखने के लिए रिएक्टरों पर ठंडे पानी की निरंतर प्रबल धाराएं छोड़ी जाती हैं। हालांकि प्राकृतिक अथवा अन्य आपदा की स्थिति में ये परमाणु संयंत्र अचूक कंप्यूटर प्रणाली से संचालित व नियंत्रित होने के कारण खुद-ब-खुद बंद हो जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में विरोधाभासी स्थिति यह होती है कि जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाभिकीय विखण्डन तो थम जाता है, किंतु रासायनिक प्रक्रियाएं और भौतिक दबाव एकाएक नहीं थमते। गोया, जलधारा का प्रवाह बंद होते ही रिएक्टरों का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेट से बढ़कर 10000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच जाता है। यह तापमान जीव-जंतुओं को तो क्या स्टील जैसी ठोस धातु को भी पल भर में गला देता है। इस लिहाज से इन संयंत्रों के संभावित खतरों को एकाएक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

सम्पूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

सम्पूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्त्व रहा है। इसलिए भारत में नदियों को मां कह कर पुकारा गया। यह उस दौर की बात है जब लोगों के दिन की शुरुआत नदियों के तट से शुरू होती थीं। प्राचीन काल से ही नदियां मां की तरह हमारा भरण-पोषण करती आ रही हैं। नदियों की वजह से सभ्यताएं रचती हैं, बस्तियां बस्ती हैं। मगर जब इंसान की जरूरत का जल नलों के जरिए घरों तक पहुंच गया तो नदियां क्या नदी, झील और कुएं आदि अपने महत्व खोने लगे। चुकी नदियों के जल के उपयोग से पुण्य और सुखों की प्राप्ति की मान्यता जुड़ी हुई है इसलिए इंसान नदियों से जुड़े अनुष्ठानों के प्रति तो जागरूक रहा लेकिन नदियों के प्रवाह के सुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ लिया। धीरे-धीरे नदियां दुर्दशा की शिकार होने लगीं। सबसे ज्यादा उपेक्षा के शिकार छोटी नदियां हुईं। चुकी उनकी प्रवाह क्षेत्र कम था इसलिए उपेक्षा ने उन्हें नालों में बदल दिया। छोटी नदियों की दूरदर्शा के कारण ही बड़ी नदियों के जलप्रवाह में कमी आई है। गंगा, यमुना, जैसी बड़ी नदियों को स्वच्छ रखने पर तो बहुत काम हो रहा है पर ये नदियां बड़ी इसीलिए बनती है क्योंकि इनमें बहुत से छोटी नदियां आ कर मिलती हैं। एक अनुमान है कि आज भी देश में कोई बारह हजार छोटी ऐसी नदियां है, जो उपेक्षित है, उनके अस्तित्व पर खतरा है। उन्नीसवीं सदी तक बिहार में कोई 6000 नदियां हिमालय से उतर कर आती थी, आज इनमें से महज 400 से 600 का ही अस्तित्व बचा है। मधुबनी, सुपौल में बहने वाली तिलयुगा नदी कभी कोसी से भी विशाल हुआ करती थी, आज उसकी जल धरा सिमट कर कोसी की सहायक नदी के रुप में रह गई है। सीतामढ़ी की लखनदेई नदी को तो सरकारी इमारतें ही चाट गई। नदियों के इस तरह रूठने और उससे बाढ़ और सुखाड़ के दर्द साथ साथ चलने की कहानी देश के हर जिले और कस्बे की है। मध्य प्रदेश की दूधी नदी को तो कुछ समय पहले बारहमासी नदी माना जाता था लेकिन अब इसका जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है । सतपुड़ा के मछवासा, आंजन ओल, पलकमती और कोरनी नदी की हालत अच्छी नहीं है। सहारनपुर की पांवधोई नदी गंदे नाले में बदल गई थी लेकिन लोगों की जागरूकता ने बुरी हालत से मुक्त कराने में सफलता पाई है पर काली हिंडन और गुनता आदि नदियां अपने उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही है।

छोटी नदी केवल पानी के आवागमन का साधन नही होती। उसके चारों तरफ समाज भी होता हे और पर्यावरण भी। नदी के किनारे किसान भी हैं और मछुआरा भी। छोटी नदियों के सेहत बिगड़ने पर तालाब से लेकर कुएं तक में जल का संकट आता है। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से समाज में ऐसा कोई वर्ग नही है जो इससे प्रभावित नही हुआ हो। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में छोटी नदियां धरती के तापमान को नियंत्रित रखने, मिट्टी की नमी बनाए रखने और हरियाली के संरक्षण के लिए अनिवार्य है। नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाने से, उसमे से बालू रेत उत्खनन को नियंत्रित करने, नदी की गहराई के लिए उसकी समय समय पर सफाई से इन नदियों को अपना मानकर सहेजने लगे तो इससे पर्यावरण के साथ समाज के लिए भला होगा। धीरे-धीरे हमारी सभ्यता एक बड़े जल संकट की ओर तेजी से बढ़ रहीं है। अगर वक्त रहते हम नही जागे तो बड़ी मुसीबत से घिर जायेंगे। छोटी नदियां बचेंगे तब ही हम बड़ी नदियों को बचा पाएंगे। इसके बिना नदी संरक्षण की कोशिशें अधूरी रह जायेंगी

एकेडमिक हाईट्स पब्लिक स्कूल में आयोजित होगी दो दिवसीय रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यशाला

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर में स्थित एकेडमिक हाईट्स पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सीबीएसई द्वारा निर्धारित नई शिक्षा नीति (NEP) एवं स्किल बेस्ड एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स पर आधारित दो दिवसीय विशेष कार्यशाला का 2 दिवसीय आयोजन दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर को विद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम का संचालन इसरो स्पेस एजुकेटर के मार्गदर्शन में किया, जिसके अंतर्गत रोबो+ एडुटेक द्वारा गुजरात से आए दो अनुभवी प्रशिक्षक अक्षित गुज्जर, जतिन वलरानी विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान प्रदान किया। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों को रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूल अवधारणाओं के साथ-साथ उनके व्यावहारिक उपयोगों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित रोचक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में नवाचार, तार्किक सोच और समस्या समाधान की क्षमता को विकसित किया गया। कार्यक्रम में विशेष बात यह है कि यह प्रशिक्षण केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विद्यालय के शिक्षकगण भी इस कार्यशाला में भाग लेकर नवीन तकनीकों की जानकारी प्राप्त किया, जिससे वे भविष्य में विद्यार्थियों को और अधिक प्रभावी एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान कर सके। विद्यालय संचालक सचिन बलवटे का मानना है कि इस प्रकार की कार्यशालाएं विद्यार्थियों को तकनीक-आधारित शिक्षा की ओर प्रेरित करती हैं और उन्हें आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करने में सहायक सिद्ध होती हैं। यह पहल एकेडमिक हाईट्स पब्लिक स्कूल की गुणवत्तापूर्ण एवं नवोन्मेषी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

परीक्षा केंद्र प्रमुखों की गलती से नवोदय परीक्षा अभ्यर्थी छात्रा का शैक्षणिक भविष्य खतरे में, जिम्मेदारों हेतु कठोर कार्यवाही की मांग

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले के गाडरवारा विकासखंड के अंतर्गत नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 के केंद्र शासकीय कन्या शाला से जुड़ा है। जहां पर आवेदक को परीक्षा दिलवाई गई जबकि उसका केंद्र शासकीय आदर्श हा.से. विद्यालय जारी किया था। ऐसे में अब उसकी परीक्षा की मान्यता परिणाम को लेकर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उक्त विषय को लेकर आवेदक के परिजनों द्वारा सी.एम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई है व मामले का त्वरित निराकरण जिससे कि आवेदक छात्रा का भविष्य सुरक्षित हो सके व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। विषय के सामने आते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी व केंद्राध्यक्ष पर सवालिया निशान है। शासकीय कन्या शाला के केंद्र अध्यक्ष सुशील शर्मा द्वारा बिना पूर्ण अनुक्रमांक जांच किए छात्रा को अपने केंद्र में परीक्षा दिलवाई गई जबकि उसका केंद्र शासकीय आदर्श बालक हा.से. विद्यालय हेतु जारी था। ऐसे में दोनों परीक्षा केंद्रों के केंद्र अध्यक्षों सुशील शर्मा व एस.के. मिश्रा की कर्तव्यों के प्रति सजगता शक के घेरे में दिख रही है। ग्राम भौंरझिर के निवासी शिकायतकर्ता विजय कौरव द्वारा बताया गया है कि आवेदक सेजल कौरव कक्षा 5वीं जो कि शिकायतकर्ता की पुत्री है। आवेदक का कहना है कि आवेदक के द्वारा नवोदय की परीक्षा दी थी पर शासकीय उच्चतर कन्या स्कूल गाडरवारा में जहां पर सेंटर आया था वहां पर शिक्षक के द्वारा गलत बिठाया गया था। जबकि सेंटर आदर्श स्कूल में आया था। छात्र के द्वारा एडमिट कार्ड भी शिक्षक को बताया गया था पर फिर शिक्षक द्वारा पेपर देने दिया है जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है।

सामाजिक संस्थान द्वारा देवरी के पीएम श्री बेसिक हाई स्कूल में 100 से अधिक बच्चों को स्वेटर प्रदान किए

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला। आश एक उम्मीद सामाजिक संस्थान द्वारा लगातार गांव गांव में स्कूली बच्चों को इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए स्वेटर प्रदान किए जा रहे हैं, इस दौरान संस्था द्वारा क्रेशर टोला, चोर धवई, उमरखोए, बेलढाना, डोंगर सलैया के स्कूलों में स्वेटर प्रदान करने के बाद देवरी के पीएम श्री बेसिक हाई स्कूल में 100 से अधिक बच्चों को स्वेटर प्रदान किए। संस्थान के अध्यक्ष संजय ब्रजपुरिया ने बताया कि इस कड़ाके की ठंड में छोटे-छोटे बच्चों को स्कूलों में कप कपाते देख संस्था के सदस्यों ने बच्चों को स्वेटर प्रदान करने का निर्णय लिया और संस्था के सदस्य लगातार गांव गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों को स्वेटर वितरित कर रहे हैं जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई कर सके, इसी क्रम में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र खल्का की अध्यक्षता में ग्राम खैरी के स्कूल में बच्चों को स्वेटर वितरित किए जाएंगे। पीएम श्री बेसिक स्कूल में स्वेटर वितरण कार्यक्रम के दौरान बीईओ शिवांग गुप्ता, बीआरसी हरिकृष्ण चौबे, आश एक उम्मीद सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष संजय बृजपुरिया, सचिव अनिल ढिमोले, धीरेंद्र मिश्रा, विजय पटेल, योगेंद्र ठाकुर, अभय दुबे, पदम कुर्मी, सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चे मौजूद रहे।

अन्नदाता

मध्यप्रदेश शासन

पराली न जलाएं, धरती और जीवन बचाएं

उपजाऊ शक्ति में वृद्धि | प्रदूषण से मुक्ति | अर्थव्यवस्था को गति

मिट्टी के रूप में मिले वरदान को नष्ट होने से बचाएं

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री — नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ये विकल्प अपनाएं

हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम यंत्र का उपयोग

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का उपयोग कर सीधी बोनी

रीपर से कटाई के बाद जीरो टिलेज मशीन से सीधे बोनी

बेलर मशीन का उपयोग कर धान की पराली और मक्के के तने के बेल्स बनाएं

धान की पराली का प्लेट्स, ब्रिक्स और बायो फर्टिलाइजर के निर्माण में उपयोग

प्राकृतिक खेती को अपनाएं

मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों के बढ़ावे से मिट्टी की उर्वर शक्ति में वृद्धि

रासायनिक पदार्थों से मुक्त होने से कैंसर जैसी घातक बीमारियों से मुक्ति

प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कोई कमी नहीं

R.O. No. : D19257/25

आइये, स्वस्थ मिट्टी, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए पराली न जलाने का प्रण लें....

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)